

प्रतिलिपि आदेशादिनांक 12-8-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिखरे सदस्य
राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर प्र०प्र० निग० 1746-तान/14 विरुद्ध आदेशा
दिनांक 30-4-14 पारित द्वारा आर कलेक्टर जिला छतरपुर म०प्र०
प्रकरणक्रमांक 476/निग०/अ-5/2007-2008 •

श्रीमती अभिषा पत्नी श्री नंदकिशोर यादव
निवासोगण राजनगर तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म०प्र० अन्य-4
विरुद्ध

--- आवेदकगण

बृजकिशोर तनय भूाना दान जहोर
निवासो ग्राम राजनगर तहसाल राजनगर
जिला छतरपुर म०प्र० अन्य-8

--- अनावेदकगण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 1746/ तीन/2014

जिला छतरपुर

स्थान तथा
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं
अभिभाषकों के
हस्ताक्षर

12.8.14

यह निगरानी अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 476/2007-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30.4.2014 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि तहसीलदार राजनगर द्वारा ग्राम की नामान्तरण पंजी पर पारित आदेश दिनांक 12-3-2007 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के समक्ष अपील की गई थी, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 28-2-2007 से तहसीलदार के विधिवत् दिये गये आदेश पर स्थगन देने में भूल की गई और जब अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण क्रमांक 28/06-07 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 28-3-07 के विरुद्ध अपर कलेक्टर के यहाँ निगरानी की गई, तब अपर कलेक्टर ने निगरानी अस्वीकार करने में त्रुटि की है क्योंकि उन्हें मामले की तह में जाकर न्यायहित में अनुविभागीय अधिकारी के स्थगन आदेश को निरस्त करना था, इसलिये निगरानी सुनवाई में लेकर अपर कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेशों के क्रियान्वयन को रोकते हुये संहिता की धारा 52 का आवेदन स्वीकार किया जावे।

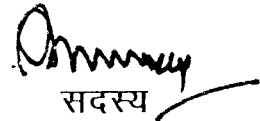
4/ प्रकरण में विचार योग्य बिन्दु है कि अनुविभागीय अधिकारी राजनगर ने अंतरिम आदेश दिनांक 28-3-2007 से तहसीलदार के आदेश

दिनांक 12-3-07 के क्रियान्वयन को स्थगित करने में किसी प्रकार की त्रुटि की है एवं अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं मानने में भूल की गई है ?

“ भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)- धारा-52 - रोक आदेश देने की शक्ति का प्रयोग - रोक का आदेश देना या न देना न्यायालय के विवेक पर निर्भर है। अपील सुनवाई हेतु ग्रहण किये जाने का तात्पर्य है कि अपीलार्थीगण के मामले में प्रथम दृष्टया कानूनी मुद्दा निहित है, तब रोक का आदेश न्यायालय स्वविवेक से दे सकेगा। ”

अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 28/06-07 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 28-3-07 का अपर कलेक्टर, छतरपुर ने भलीभाँति परीक्षण कर निष्कर्ष दिया है कि अनुविभागीय अधिकारी अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 28-3-07 में किसी भी दृष्टिकोण से दोष नहीं है और उन्होंने आदेश दिनांक 30.4.2014 से निगरानी निरस्त की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-4-2014 विधिवत् पाये जाने से निगरानी अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।


सदस्य